number of frauds and amount involved therein for the years 1985, 1986 and 1987, as reported Reserve Bank of India by public sector banks, irrespective of the dates of occurence, is given below:—

Year	No. of frauds	Amount involved (Rs. in lakhs)
1985 . .	2157	5348 02
1986 . .	1822	4441.78
198 . .	1902	4984.34

(Data provisional)

Information in respect of cases of frauds involving Rs. 20 lakhs and above is not readily available separately.

RBI has reported that during the years 1985, 1986 and 1987 the following number of bank officials have been punished for their involvement in cases of frauds and corruption:

	Fraud Cases		
	1985	1986	1987
(1) Awarded major/minor penalties	720	683	874
(2) Dismissed/discharged/removed from service out of (1) above	270	291	338

(Data provisional)

	(Corruption Cases)		
	1985	1986	1987
(1) Awarded major/minor penalties	428	454	604
(2) Dismissed/discharged/removed from service out of (1) above	116	115	118

(Data provisional)

(c) Banks are taking steps to strengthen the control mechanisms, including the internal audit/inspection machinery and to make them effective so as to eliminate the scope for frauds and malpractices. Banks have been taking a serious view of irregularities committed by their employees and initiate action to inflict punishment befitting the seriousness of irregularities on the delinquent employees. They have been taking steps to tone up control and supervision. mental enuiries. Banks have reviewed and revamped the vigilance machinery, taken steps to one up control and supervision, strengthen management information system, follow up and inspection/audit arrangements and for clearing the arrears in balancing of books and reconciliation of inter-branch and and other accounts on a continuous basis so as to prevent frauds in these areas.

"वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों में रुकावट"

804. **श्री अजीत जोगी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पेश आ रही कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार शाला-भवन, पहुंच मार्ग, सामुदायिक भवन, नलकूपों आदि से संबंधित विकास-कार्यों के लिये इन जनजातीय क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुछ छूट प्रदान करने का विचार रखती है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य के कार्यान्वयन में महसूस की गई कठिनाइयों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं। इस प्रकार के मामलों में विलम्ब मुख्य रूप से पहली बार में वांछित सूचना पूर्ण रूप में न भेजने के कारण हुआ। अपेक्षित सूचना भेजने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, ताकि शीघ्र निर्णय लेने में सुविधा हो।

(ग) जी, नहीं।

वृक्षों को कटाई पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

865. **श्री अजीत जोगी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनों की कटाई तथा लकड़ी की चोरी को रोकने के लिये देश के कुछ वन-प्रधान राज्यों में, भविष्य में, वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार उन राज्यों को जो स्वत: अपने वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेंगे, पर्याप्त सहायता अथवा मुआवजा प्रदान करने का विचार रखती है, ताकि इसके कारण उन्हें होने वाली राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने दिसम्बर, 1987 में हुई अपनी 22वीं बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प अपनाये :—

1. वनों के संरक्षण के लिये लकड़ी की निकासी को रोका जाये ;

2. इसके परिणाम स्वरूप राज्य राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति की जायेगी क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण वित्त आयोग करेगा।

इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और इससे राजस्व की कितनी हानि होगी, इस बारे में उनसे ब्यौरे मांगे गये हैं। क्षतिपूर्ति के मामले को वित्त आयोग के साथ उठाया गया है।

Closure of a NTC Mill in Gulbarga

866. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the M.S.K. Mill, Gulbarga belonging to NTC has been closed down rendering more than 2,000 workers unemployed : and

(b) if so, since when it is lying closed, the compelling reasons for the closure and the effort made or being made to reopen the Mill?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Mahboob Shahi Gulbarga Mills, Gulbarga is closed since 1-6-1988 as a result of disconection of power supply by the Karnataka Electricity Board. NTC has declared a lay-off in the mill.

(b) The question of reopening of the mill is before the Karnataka High Court and is, therefore, subjudice.

Jewellery found Missing from a Bank Locker

867. SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI RAM AWADHESH SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gold and diamond jewellery worth lakhs of rupees was found missing from a locker of a nationalised bank in North Delhi recently:

(b) if so, what are the details thereof;